वर्ष-9 अंक-2 फरवरी 2019 मूल्य 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

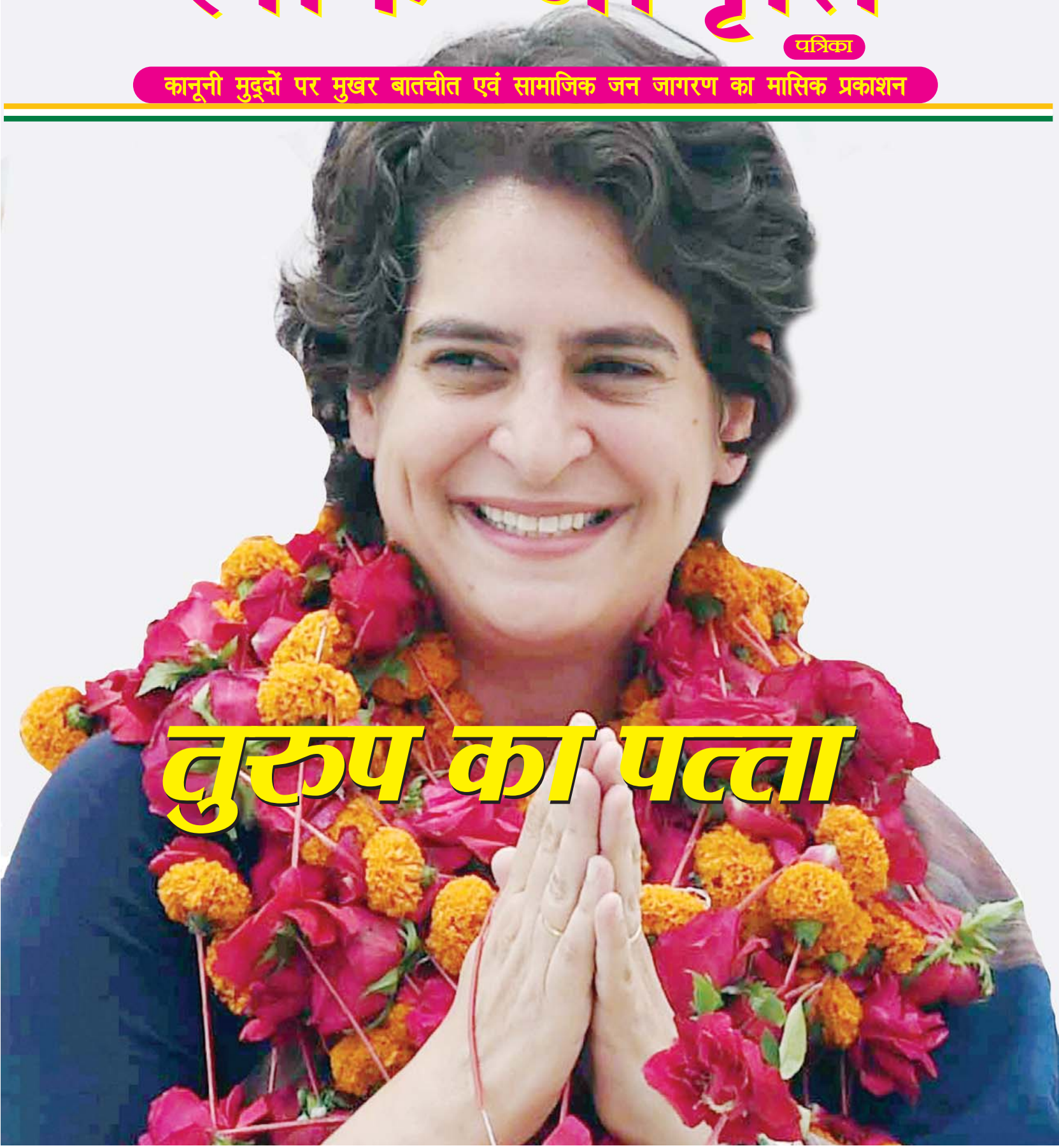

तुरुप का पत्ता

लोक जागृति संस्था की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं

सुरेश पाण्डेय
राष्ट्रीय अध्यक्ष
ग्लोबल पीस एण्ड हारमोनी फाउण्डेशन
दिल्ली फ्रेंड्स फाउण्डेशन

पं. दयानंद शुक्ला

S.K. MISHRA
Advocate, (Chief Editor
LOK JAGRITI PATRIKA)
Mob-9560522777, 9810960818

Add.: IIIA/95 Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010

lokjagriti@gmail.com, www.lokjagriti.com

Suresh Pandey **9810514888**

INDIAN/FOREIGN BOOKS,JOURNALS

NEW/OLDLAW BOOKS

BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIES

SK

SK ACADEMY PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4 West Vinod Nagar, Delhi-110092

mail- suresh66pandey@gmail.com, pandeysureshk@gmail.com

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10–सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11–लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12–बड़े नोट 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13–हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14–भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15–समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16–देश के प्राकृतिक संसाधनो पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17–सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18–कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19–गरीबों की सही पहचान और लोगों को रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20–टोल टैक्स समाप्त करना।

अंदर के पृष्ठों पर...

1	कवर स्टोरी	6–8
2	कुंभ	9–14
3	सुप्रीम कोर्ट हुआ तल्ख	16
4	इन सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड	18
5	आर्थिक आधार पर आरक्षण का मार्ग प्रशस्त	19
6	जीवन सफर में बढ़े जा रहा हूं	20
7	बजट में सपने ज्यादा सच कम	21–22
8	नागरिकता संशोधन विधेयक	23
9	आखिर क्यों उलझी दीदी	24
10	इलाहाबाद यूनिवर्सिटी	25
11	दुनिया को देश की ताकत दिखाई	26–27
12	वकीलों की मांग	28

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका

95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010

lokjagriti@gmail.com, 9560522777

www.lokjagriti.com

सियासी फलक पर उतरीं प्रियंका गांधी

करीब 28 साल पहले पिता राजीव गांधी की अंतिम यात्रा में आम लोगों के साथ चलकर देश की जनचेतना में पहली बार दस्तक देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस वक्त अपनी सक्रिय सियासी पारी का आगाज कर दिया जब उन्हें कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। गांधी–नेहरू परिवार की समृद्ध राजनी. तिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका सक्रिय राजनीति में कदम रखने से पहले करीब दो दशक तक राजनी. तिक बारीकियों से रूबरू हुईं। लंबे समय तक सियासी गलियारों में इस पर चर्चा होती रही कि आखिर प्रियंका सक्रिय राजनीति में कब कदम रखेंगी और पार्टी में बड़ी भूमिका निभाएंगी। उनके भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए लोकसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले प्रियंका को कांग्रेस महासचिव और प्रभारी (उत्तर प्रदेश–पूर्व) नियुक्त किया और इसी के साथ सक्रिय राजनीति में प्रियंका के सफर का आगाज हो गया।

अभी तक 47 साल की प्रियंका खुद को कांग्रेस की गतिविधियों से अलग रखते हुए अपने परिवार के लिए काम करती रही हैं। उनका दायरा अब तक विशेष तौर पर मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों रायबरेली एवं अमेठी तक सीमित रहा है। प्रियंका का जन्म 12 जनवरी, 1972 को हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली प्रियंका की राजनी. तिक गतिविधि की शुरूआत 1998 में मां सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद हुई। 1999 के आम चुनाव में सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी सीट से एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ीं। इस दौरान प्रियंका ने अमेठी के प्रचार की कमान संभाली। सोनिया ने 2004 में अमेठी की सीट पुत्र राहुल गांधी के लिए छोड़ी और खुद रायबरेली चली गईं। इसके बाद प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी दोनों क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी संभाली।

भाजपा ने जब राजीव गांधी के करीबी रहे अरुण नेहरू को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया तो प्रियंका ने वहां की जनता के समक्ष जो वो कहा वो बड़ी सुर्खियां बना। उस वक्त प्रियंका ने कहा, ''मुझे आपसे से शिकायत है। एक व्यक्ति जिसने गद्दारी की और जिसने अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपा, आप ऐसे व्यक्ति को यहां कैसे रहने दे सकते हैं? उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई?'' वह अक्सर रायबरेली का दौरा करती रहती हैं और चुनाव के समय वह कई दिनों तक प्रचार करती रही हैं। कई मौकों पर अपने भाई राहुल गांधी का खुलकर बचाव करती आई हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका उदाहरण भी देखने को मिला जब मोदी लहर के बीच भाजपा ने स्मृति ईरानी को अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में उतारा तो प्रियंका ने अपने भाई के पक्ष में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया और जीत सुनिश्चित की। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए गुजरात मॉडल पर तंज किया था। प्रियंका को करीब से जानने वालों का कहना है कि वह मृदुभाषी होने के साथ कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देती हैं तथा सबकी बात सुनने में विश्वास रखती हैं। रायबरेली में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ''हम प्रियंका जी को वर्षों से देख रहे हैं। उनका कार्यकर्ताओं और आम लोगों से खासा जुड़ाव है। वह सबके साथ संवाद करती हैं और वह कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क में रहती हैं।'' उन्हें जिस उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र वाराणसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहे जाने वाला गोरखपुर भी आता है। कहा जाता है कि प्रियंका बौद्ध दर्शन का अनुसरण करती हैं और विपश्यना भी करती हैं। मॉडर्न स्कूल और 'कानवेंट ऑफ जीसस एंड मैरी' से स्कूली पढ़ाई करने वाली प्रियंका ने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक किया। प्रियंका ने बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर किया। पार्टी नेताओं को लगता है कि प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतरने से कांग्रेस को पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश में फायदा होगा। (लोक जागृति टीम)

लोक जागृति पत्रिका

फरवरी 2019 वर्ष 9 अंक 2

संरक्षक

पं। दयानंद शुक्ला
कपिल सिंघल
ए.जी. अग्रवाल

संपादक

संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल

समाचार संपादक

आलोक सोलंकी
बृजमोहन

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय
विजय बहादुर सिंह
तेज सिंह यादव (एडवोकेट)
नरेन्द्र कुमार सक्सेना
गिरीश त्रिपाठी
एस.बी.एस. गौतम
सत्येंद्र श्रीवास्तव
अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)
राहुल मिश्र
जगजीत सिंह
कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)
राजेश कुमार मिश्र
तरुण गुप्ता (एडवोकेट)
शोभा चौधरी
अनिल कुमार शुक्ला
रजनीश कुमार पाण्डेय
धीरज पाण्डेय
प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग

संजय मिश्रा

कानूनी सलाहकार

अभिषेक शर्मा

साज सज्जा
A.N.R. Creation
7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक
संतोष कुमार मिश्रा
द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

प्रजातंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर के रुप में होता है और चुनाव का आगाज हो चुका है। हवाई रैलियों के साथ राजनीतिक लोगों द्वारा हवाबाजी चालू है। देश की जनता के साथ पूरी तरह राजनीति होती रही है और होती रहेगी। उसे कोई रोक नहीं पाएगा। राजनीतिक लोगों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने को साफ सुथरा साबित करते रहेंगे। दूसरों का हिसाब पूछा जाएगा अपने चुनाव खर्च एवं आरोपों का जवाब कतई नहीं दिया जाएगा।

कालेधन की बात की जाएगी लेकिन चुनाव में जनता के सामने कालेधन का खुलेआम उपयोग किया जाएगा। चुनाव के मौसम में कभी राफेल कभी बोफोर्स रुपी ओले भी पड़ेंगे लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों का पिटारा मिलेगा और चुनाव बाद महंगाई का तोहफा क्योंकि चुनाव का सारा खर्च नेता को निकालना है तो वह जनता से ही लिया जाएगा। साथ में एक पद पा जाने के बाद सात पुस्तों साथ रिश्तेदारों को भी मालामाल कर देना फिर मौका मिले न मिले।

भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता है इसका मुख्य कारण है कि भ्रष्टाचार की परिभाषा बहुत व्यापक है यहां जिस तरह से कानून का भ्रम जाल बिछा हुआ है किसी भी व्यक्ति या संस्था को भ्रष्ट सिद्ध किया जा सकता है। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे भ्रष्टाचार का पता किया जा सकें, लेकिन भ्रष्टाचार प्रजातंत्र के लिए खतरनाक होता है जब उससे जनता के जीवनस्तर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवश्यक आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचे। जनता का विश्वास संवैधानिक संस्था से खत्म हेा जाए। प्रजातंत्र के चार स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एवं मीडिया माने जाते हैं और इन चारों स्तंभों के बारे में यदि आप स्वयं दस लोगों से सर्वे करे तो पता लग जाएगा कि इनमें अब जनता की कितनी विश्वसनीयता है।

जब भ्रष्टाचार की जांच करने वालों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो तो यह कितनी बुरी स्थिति होगी। सीबीआई अधिकारियों की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और सीबीआई की जिस तरह से कार्यप्रणाली चल रही है वह लोगों के लिए हास्यपद बन कर रह गई है। शिक्षण संस्थाओं का पूरी तरह राजनीतिकरण किया जाता है। वह भी एक चिंताजनक है। पहले पूरी जांच पड़ताल तथा स्क्रीनिंग करके किसी को दो या तीन वर्ष के लिए आप पद देते हैं और उसके बाद आप स्वयं उसे काम नहीं करने देते जांच पर जांच कराते हैं। यह क्या है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग है कि हम बैठा दिए हैं हमारी कठपुतली बने रहोगे तो पद पर बने रहोगे नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। यदि भ्रष्ट था तो उसे नियुक्त क्यों किया!

बेरोजगारी एवं बीमारी इस समय बहुत बड़ी समस्या है लेकिन इसको दूर करने के लिए न तो कोई ठोस नीति है और न नीयत ही यह उसे ही झेलना है जो इससे पीड़ित है। कल कारखानों अस्पताल की जगह जब प्राथमिकता और दूसरी चीजों पर हो तो यही होगा। उसके अलावा बेरोजगारी को खत्म करने का सुलभ जड़ी बूटी 'आरक्षण' है दे दो तो सभी बेरोजगारों को अपने आप रोजगार मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि यह तो सभी जानते हैं इस समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले और क्या किया जाए! इसी सब का हल ढूंढने एवं नीति निदेशकों को कुछ सचेत करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी हाल में सीआरपीएफ जवानों के ऊपर जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ बहुत ही दर्दनाक एवं कायरतापूर्ण कार्य रहा है। इसके पहले भी कई हमले सेना के कैम्प पर हुए हैं लेकिन सरकार सिर्फ बयान बहादुर बन कर मामले पर राजनीति करने लग जाती है। अमेरिका ने जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को मारा भारत को उसी तरह से आतंकवादियों के आकाओं को मारकर बयान देना ही सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता।

प्रियंका गांधी क्या अगली इंदिरा गांधी हो सकती हैं?

साल 1999, रायबरेली। चुनावी मुहिम ज़ोर–शोर से जारी थी। कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन सतीश शर्मा मैदान में थे तो बीजेपी की तरफ़ से राजीव गांधी के चचेरे भाई अरुण नेहरू।

उस वक़्त 27 साल की एक नौजवान महिला कांग्रेस का प्रचार कर रही थी। उन्हें देखने काफ़ी भीड़ जमा हो जाती थी। अरुण नेहरू रायबरेली से पहले भी चुनाव जीत चुके थे।

अरुण नेहरू की वजह से रायबरेली में बीजेपी के लिए माहौल बनता हुआ दिख रहा था। ऐसे में उस 27 साल की लड़की ने एक चुनावी रैली के बीचोबीच सवाल पूछा, "मेरे पिता जी से दग़ाबाज़ी करने वालों को आपने यहां पर घुसने कैसे दिया।" उन्होंने आगे कहा, ''क्या आप उन्हें वोट देंगे जिन्होंने मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपा।'' बस बयान की काफ़ी चर्चा हुई और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनी गई।

दूसरे दिन अरुण नेहरू के प्रचार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी रायबरेली पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण में उस लड़की के बयान पर काफ़ी हल्के–फुल्के ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी। "हमने सुना कि ये किसी का इलाक़ा है। आपने इस आदमी को घुसने कैसे दिया।"

इसके बाद चुनाव प्रचार काफ़ी ज़ोर–शोर से चला और कहा जाने लगा कि मुक़ाबला कांटे का हो गया है लेकिन उस एक लाइन ने अमेठी–रायबरेली चुनाव की कहानी बदल दी थी। शुरु में कांटे की टक्कर देने वाले अरुण नेहरू चौथे नंबर पर चले गए और कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा जीत गए। कैप्टन सतीश शर्मा के लिए प्रचार करने वाली ये लड़की थीं प्रियंका गांधी।

प्रियंका गांधी औपचारिक तौर पर सक्रिय राजनीति में आ गईं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की ज़िम्मेदारी प्रियंका को सौंपी गई है।

पूरा दिन मीडिया में इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी के बीच समानताओं पर बात चलती रही। दोनों के पहनावे,

चाल–ढाल, आक्रामकता, वाक़पटुता और तंज भरे लहज़े में बात कहने की कला, जैसे पहलुओं पर दिन भर लोग बात करते रहे।

और ये सवाल उठा कि क्या प्रियंका गांधी इंदिरा की तरह प्रियदर्शीनी हैं। क्या वे इंदिरा की तरह राजनीति में अपना असर छोड़ने में कामयाब हो पाएंगी। राजनीतिक विश्लेषक राशीद किदवई कहते हैं, "इंदिरा गांधी के ज़माने में अलग तरह से राजनीति होती थी, चुनौतियां भी अलग थीं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का काम करने का तरीका अलग था।''

''उनकी राजनीति का ढंग भी अलग था। साथ ही उनका लोगों के बीच जाकर उन्हें समझने का तरीका भी अलग था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बीच भी इसी तरह फ़र्क था, वही फर्क राजीव गांधी और सोनिया गांधी की कार्यशैली में भी है। ऐसे में इंदिरा गांधी और प्रियंका की राजनीति की प्रकृति और शैली में भी अंतर है।"

किदवई आगे कहते हैं, "इंदिरा और प्रियंका के पहनावे में बहुत समानता है। उनकी बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं। वह कहते हैं कि इंदिरा लोगा. ` को अपनी–सी लगती थीं। वह सहजता से लोगों में घुलमिलकर बातें करती थीं।''

इंदिरा के चेहरे पर लोगों को ऐसी उम्मीद नज़र आती थी कि वह देश के लिए कुछ कर सकती हैं। उनमें विनम्रता भी थी। प्रियंका इन चीज़ों में इंदिरा से काफ़ी मिलती–जुलती हैं। वह भी लोगों से अच्छे से बातें करती हैं। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी की जो अपील थी लोगों के बीच, वैसी ही अपील प्रियंका की है। ऐसे में प्रियंका के आने के कारण उत्तर प्रदेश में कुछ फ़र्क तो नज़र आएगा। वहां पर बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अभी भी इंदिरा गांधी को मानता है। प्रियंका के चेहरा, उनकी शैली और पहनवाने से लोगों को ऐसा लगेगा कि इंदिरा उनके बीच हैं।

तो क्या इंदिरा जैसी नज़र आने वालीं प्रियंका उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए क्या यह काफ़ी है? मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सोशल इंजिनियरिंग के पैटर्न को क्या वह मात दे सकती हैं? इन सभी सवालों और उत्तर प्रदेश में सत्ता के संघर्ष को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं, "प्रियंका जी भले ही इंदिरा गांधी जैसी नज़र आती हों, उनका हेयरस्टाइल और पहवाना उन जैसा हो मगर राजनीति में यह सब ज़्यादा दिन नहीं चलता।'' (साभार : बीबीसी)

यदि शांति चाहते हो तो लोकप्रिय होने से बचो।

प्रियंका गांधी एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला

नेहरू–गांधी परिवार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना–पहचाना नाम है। सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में से एक माना जाता है। उसी परिवार से नाता रखने वाली प्रियंका गांधी एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला हैं।

राजनीति के माहौल में पली बढ़ी प्रियंका बचपन से ही इसमें रची बसी हैं। राजीव–सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका का जन्म 12 जनवरी 1972 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के मॉर्डन स्कूल कान्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी से की और नई दिल्ली के जीजस एंड मैरी महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है। मनोविज्ञान में बीए कर चुकीं प्रियंका की हिन्दी साहित्य में गहन रूचि है। इसका श्रेय वह अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन को देती हैं। उन्होंने ही प्रियंका को इतनी अच्छी हिन्दी सिखाई। वे प्रियंका को श्री हरिवंशराय बच्चन की कविताएं सुनाती थीं और प्रियंका को उन्हें पढ़ने को कहती थीं। 18 फरवरी सन् 1997 में उनकी शादी दिल्ली के उद्योगपति रॉबर्ट वडेरा से हुई। उनकी पहली मुलाकात एक मित्र ओटेवियो क्वट्रोच के घर हुई थी। 29 अगस्त सन् 2000 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद उन्होंने 24 जून 2002 को एक बेटी को जन्म दिया। जिनके नाम रेहान व मिराया है। कई बार चुनाव अभियान में प्रियंका अपने बच्चों के साथ दिखाई देती हैं। शादी के बाद खुद को प्रियंका गांधी कहलाना उन्हें नहीं भाता। एक रोड शो के दौरान उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा था कि कृपया मुझे प्रियंका वडेरा कहें । अपने भाई राहुल गांधी से उम्र में छोटी प्रियंका बचपन से ही काफी स्मार्ट हैं। सुंदर नैन–नक्श वाली प्रियंका अपनी दादी की छवि हैं। उनका दमदार व्यक्तित्व भी दादी की तरह है। यह गर्व की बात है कि उनके पिता राजीव गांधी, दादी श्रीमती इंदिरा गांधी और दादी के पिता जवाहरलाल नेहरु तीनों ही भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक सफल और सक्रिय राजनीति घराने से संबंध रखने वाली प्रियंका अपना भविष्य राजनीति में नहीं बनाना चाहतीं। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब न में ही रहा।

उनका मानना है किराजनीति का मतलब सिर्फ लोगों की सेवा करना है और यह मैं पहले से कर रही हूं। गौरतलब है कि वे अपनी मां और भाई को चुनाव अभियान में

मदद करती हैं। उनकी सबसे अधिक सक्रियता 2004 के उत्तरप्रदेश चुनाव में देखी गई थी। रायबरेली और अमेठी में वे अपने भाई राहुल, मां सोनिया गांधी के साथ जनसंपर्क में जाती रही हैं। कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में प्रियंका के आने पर खासी भीड़ इकट्ठा होती है। अमेठी में प्रियंका की चर्चा इस कदर है की चुनाव न लड़ते हुए भी उनके नाम से स्लोगन लिखे जाते हैं। 'अमेठी का डंका बेटी प्रियंका'।

वे एक अच्छी इलेक्शन आर्गेनाइजर और अपनी मां की सलाहकार भी हैं। अपनी मां और भाई की राजनीतिक सलाहकार के अलावा वे राजनीति में कोई जगह नही चाहतीं। उनकी प्राथमिकता उनके बच्चे और परिवार है।

प्रियंका की राजनीतिक सक्रियता और परिवार के बीच उनका तालमेल आज बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायी है, लेकिन भारत को इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका के दमदार नेतृत्व का इंतजार है।

1– प्रियंका गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 16 साल की उम्र में दिया था। खबरों की मानें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका धार्मिक नगरी बनारस से चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन मोदी के खिलाफ खड़े होने के जोखिम से उन्हें बचने की सलाह दी गई;।

2– प्रियंका दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ी हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी स्कूल से साइकॉलोजी की डिग्री हासिल की।

3– प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से 13 साल की उम्र में मिली थीं। प्रियंका ने ही रॉबर्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था।

4– प्रियंका पहले काफी गुस्सैल स्वभाव की थीं लेकिन अब उनके व्यवहार की सौम्यता सबको आकर्षित करती है। इसकी वजह है प्रियंका का रोज नियम से 1 घंटे योग करना।

5– दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका ने अपनी पढ़ाई घर से ही जारी रखी। इसके बाद उनकी सामजिक जिंदगी बहुत सिमट गई। उन्हें 24 घंटे सुरक्षाकर्मियों के साये में रहना पड़ता था।

6– गांधी परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया लेकिन दादी इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका भी अपने प्यार के लिए अड़ गईं। आखिरकार परिवार को हामी भरनी ही पड़ी।

8– प्रियंका और रॉबर्ट की शादी काफी लो–प्रोफाइल रखी गई। शादी में महज 150 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया। इन मेहमानों में बच्चन परिवार भी शामिल था।

9–प्रियंका की तुलना अक्सर उनकी दादी इंदिरा गांधी से होती है। प्रियंका का हेयरस्टाइल, कपड़ों के चयन और बात करने के सलीके में इंदिरा गांधी की छाप साफ नजर आती है। (साभार : बीबीसी)

लखनऊ के रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा पर रहीं सबकी निगाहें

विजय त्यागी

कांग्रेस के पूर्वी उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले दौरे पर गईं प्रियंका गांधी पर सोमवार को कई लोगों की नजरें रहीं। आम लोगों, राजनीतिक विश्लेषकों, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और लखनऊ में उनके पहले रोड शो में शामिल हुए कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं की नजरें उन पर टिकी रहीं। इतना ही नहीं, केंद्र एवं उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा भी प्रियंका के हर एक कदम पर नजरें गड़ाए हुए है। बहरहाल, प्रियंका के लिए राजनीति एवं परिवार और सार्वजनिक एवं निजी जीवन की सीमा रेखाएं उस वक्त धुंधली पड़ती दिखी जब भाजपा के एक सांसद ने उनके कपड़ों को लेकर महिला विरोधी टिप्पणी कर दी।

उत्तर प्रदेश के बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पत्रकारों से कहा कि प्रियंका जब दिल्ली में रहती हैं, तो जींस और टॉप पहनती हैं। जैसे ही वह क्षेत्र में जनता के बीच जाती हैं तो वह साड़ी और सिंदूर लगाकर आती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने महिला विरोधी टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद की आलोचना की। प्रियंका के लखनऊ के कार्यक्रम में एक बात गौर करने लायक रही कि कांग्रेस महासचिव के तौर पर पहला रोड शो करने के बाद भी उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया और न ही सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी की।

प्रियंका ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दस्तक दी और 'लॉग इन' करने के कुछ ही घंटों के भीतर उनके 95 हजार से अधिक 'फॉलोवर' हो गए। द्विवेदी की महिला विरोधी टिप्पणी संभवतः उसी बदले की भावना वाले और जहरीले राजनीतिक माहौल की तरफ इशारा कर रही थी जिसके खिलाफ प्रियंका के पति वाड्रा ने उन्हें आगाह किया। एक फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने प्रियंका को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'भारत के लोगों की सेवा और उत्तर प्रदेश में आपके काम के नए सफर पर आपको मेरी शुभकामनाएं पी (प्रियंका)। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त, परफेक्ट पत्नी और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मां रही हैं।'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के बहनोई वाड्रा ने कहा, 'बदले की भावना वाला और जहरीला राजनीतिक माहौल है...लेकिन मैं जानता हूं कि लोगों की सेवा करना उनका कर्तव्य है और अब हम उन्हें भारत के लोगों को सौंपते हैं। कृपया उन्हें सुरक्षित रखें।'

विदेश में संपत्तियां खरीदने और राजस्थान के बीकानेर में जमीन आवंटन से जुड़े मामलों में वाड्रा के खिलाफ जांच चल रही है। पिछले हफ्ते वह पूछताछ के सिलसिले में तीन बार ईडी के समक्ष पेश हुए। साल 1997 में वाड्रा से शादी करने वाली प्रियंका ने बीते अपने पति का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा था, वह मेरे पति हैं, वह मेरा परिवार हैं...मैं अपने परिवार का समर्थन करती हूं।

प्रियंका को अपने पति को ईडी के दफ्तर तक छोड़ने आई थीं। लखनऊ में प्रियंका की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई बुजुर्गों ने कहा कि प्रियंका में अपनी दादी इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है। प्रियंका ने अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ राज्य में पहले भी चुनाव प्रचार किए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस महासचिव के तौर पर रोड शो करने के बावजूद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोला। जब प्रियंका का रथ आगे बढ़ रहा था, उत्साही लोग और पार्टी कार्यकर्ता उनकी एक अदद तस्वीर लेने के लिए बेसब्र दिखे।

प्रियंका के रथ पर रास्ते में खड़े सैकड़ों कार्यकर्ता गुलाब और गेंदे के फूलों की वर्षा करते दिखे। कुछ पोस्टरों में प्रियंका को शेर पर सवार 'दुर्गा माता' के अवतार में दिखाया गया। होर्डिंगों और बैनरों पर लिखा नजर आया, मां दुर्गा का रूप बहन प्रियंका जी का लखनऊ आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके आगे की लाइन है, दहन करो झूठे मक्कारों की लंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका...। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने 'प्रियंका सेना' भी बना ली। उन्हें गुलाबी रंग की टी–शर्ट पहने देखा गया जिस पर प्रियंका की तस्वीर थी। इससे पहले, भाजपा सांसद द्विवेदी की टिप्पणी की निंदा करते हुए मोइली ने ट्वीट किया कि लिंगभेदी और अनुचित टिप्पणियां पुरुषवादी और महिला विरोधी मानसिकता'' दर्शाती हैं। महबूबा ने कहा कि कोई महिला क्या पहनना पसंद करती है, इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जम्मू–कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा कि दुखद है कि आज की आधुनिक दुनिया में भी पितृसत्ता और लिंगभेद हमेशा अपना बदसूरत सिर उठा लेते हैं और इसे आम बना दिया गया है।

क्या है पृथ्वी पर लगने वाले सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले कुंभ का महत्व ?

कुंभ मेला पृथ्वी पर लगने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। यह प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी महाकुंभ पर्व मकर संक्रांति के दिन से इलाहाबाद में शुरू हो रहा है। पृथ्वी पर लगने वाला यह सबसे बड़ा मेला खगोल गणनाओं के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन से ही प्रारम्भ होता है। इस दिन को विशेष रूप से मांगलिक माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। किसी भी श्रद्धालु के लिए यह जीवन में महत्वपूर्ण मौका होता है जब वह पवित्र नदी में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के साथ ही एक ही स्थल पर सभी संतों, दार्शनिकों, गुरु, चेलों, संस्कृति तथा धर्म के प्रचारकों के दर्शन भी प्राप्त कर सकता है।

कुंभ मेले में अखाड़ों द्वारा किया जाने वाला शाही स्नान मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों की ओर से भव्य झांकी निकाली जाती है और प्रत्येक एक दूसरे से ज्यादा भव्यता दिखाना चाहता है। शाही स्नान करने जाते समय साधु–संत अपनी अपनी परंपरा अनुसार हाथी या घोड़े पर सवार होकर बैंड–बाजे के साथ या फिर राजसी पालकी में निकलते हैं। इस दौरान आगे–आगे नागाओं की फौज होती है और उसके पीछे महंत, मंडलेश्वर, महा मंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। इस बार पहला स्नान 15 जनवरी को और अंतिम 04 मार्च को पड़ रहा है। साधुओं के स्नान के बाद ही आम लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। हिन्दू धर्म में अखाड़ों के शाही स्नान के बाद संगम में डुबकी लगाने का बड़ा धार्मिक महत्व है। कुंभ पर्व में आम श्रद्धालु एक से पांच बार डुबकी लगाता है, जबकि अखाड़ों के नागा तो एक हजार आठ बार तक नदी में डुबकी लगा जाते हैं। प्रत्येक बारहवें वर्ष त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाले पूर्ण कुंभ के बारे में पद्म पुराण में माना गया है कि इस दौरान जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तीर्थों में संगम को सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है। इस संगम स्थल पर ही अमृत की बूंदें गिरी थी इसीलिए यहां स्नान का महत्व है। यहां स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यहां पर लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान भी करते हैं।(एजेंसी)

4 जगहों पर लगता है कुंभ

शास्त्रों के अनुसार चार विशेष स्थान है, जिन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार और प्रयाग में गंगा नदी के तट पर।

■ सबसे बड़ा मेला कुंभ 12 वर्षो के अन्तराल में लगता है और 6 वर्षो के अन्तराल में अर्द्ध कुंभ के नाम से मेले का आयोजन होता है। वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले प्रयाग में अर्द्ध कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है।

■ इसके बाद साल 2022 में हरिद्वार में कुंभ मेला होगा और साल 2025 में फिर से इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन होगा और साल 2027 में नासिक में कुंभ मेला लगेगा।

■ शास्त्रों के अनुसार चार विशेष स्थान है, जिन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर और प्रयाग में तट पर।

कब से हो रहा है कुंभ मेला

कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो हजारों साल पहले से हो रहा है। लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग के लेख से मिलता है जिसमें छठवीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का प्रसंगवश वर्णन किया गया है।

प्रत्येक तीन वर्ष में आता है कुंभ

नासिक,उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग इन जगहों पर हर 3 साल के अंतराम में कुंभ का आयोजन होता है, इसीलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन होता है।

अर्धकुंभ क्या है?

■ अर्ध का अर्थ है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच 6 साल के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक ग्रंथों में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है।

■ कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जानें वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है।

उज्जैन के कुंभ को कहते हैं सिंहस्थ

■ सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ लगता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि यह योग 12 साल में बनता है।

कुंभ पर्व और ग्रहों का संयोग

हरिद्वार

हरिद्वार का सम्बन्ध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच छह वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है।

प्रयाग

प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 वर्षो के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिषशास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है।

■ अन्य मान्यता अनुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चन्द्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होनें पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है।

नासिक

■ 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्रयम्बकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुकुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है।

■ अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चन्द्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर

हिन्दू धर्म विश्व में सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भी है.

भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है।

उज्जैन

सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है।

कुंभ पर्व क्यों मनाया जाता है?

■ कलश को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है। देवता–असुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रह थे तब उसकी कुछ बूंदें धरती की तीन नदियों में गिरी थीं। जहां जब ये बूंदें गिरी थी उस स्थान पर तब कुंभ का आयोजन होता है। उन तीन नदियों के नाम हैः– गंगा, गोदाव. री और क्षिप्रा।

■ अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार बारह दिन तक युद्ध हुआ था। जो मनुष्यों के बारह वर्ष के समान हैं। अतएव कुंभ भी बारह होते हैं। उनमें से चार कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और आठ कुंभ देवलोक में होते हैं।

■ समुद्र मंथन की कथा के अनुसार कुंभ पर्व का सीधा सम्बन्ध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है। इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12वें वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है।

■ युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी, अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र–सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, तब कुंभ का योग होता है और चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।

■ अर्थात अमृत की बूंदे छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति के विशिष्ट योग के अवसर रहते हैं, वहां कुंभ पर्व का इन राशियों में गृहों के संयोग पर आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चन्द्रमा के विशेष प्रयत्न रहे थे। इसी कारण इन्हीं गृहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परम्परा है।

■ अमृत की ये बूंदें चार जगह गिरी थीः– गंगा नदी (प्रयाग, हरिद्वार), गोदावरी नदी (नासिक), क्षिप्रा नदी (उज्जैन)। सभी नदियों का संबंध गंगा से है। गोदावरी को गोमती गंगा के नाम से पुकारते हैं। क्षिप्रा नदी को भी उत्तरी गंगा के नाम से जानते हैं, यहां पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है।

ब्रह्म पुराण एवं स्कंध पुराण के 2 श्लोकों के माध्यम इसे समझा जा सकता है।

।विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भगीरत्यभिधीयते।'।

'एव मुक्त्वाद गता गंगा कलया वन संस्थिता गंगेश्वेरं तु यः पश्येत स्नात्वा शिप्राम्भासि प्रिये।।(एजेंसी)

प्रयाग में सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ सम्पन्न हुआ था

सृष्टिकर्ता सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहाँ भगवान श्री ब्रम्हा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ सम्पन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विरा. जमान हैं। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहबाद, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा था, इसीलिए इन चार स्थानों पर ही कुंभ मेला हर तीन बरस बाद लगता आया है। 12 साल बाद यह मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। जबकि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 बीसी में शुरू हुआ था। कुंभ मेले के आयोजन का प्रावधान कब से है इस बारे में विद्वानों में अनेक भ्रांतियाँ हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्धकुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं। परन्तु प्रमाणित तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन 617–647 ई. के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने दसनामी संन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की।

राशियों और ग्रहों से कुंभ का संबंध

कुंभ मेला किसी स्थान पर लगेगा यह राशि तय करती है। कुंभ के लिए जो नियम निर्धारित हैं उसके अनुसार प्रयाग में कुंभ तब लगता है जब माघ अमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरू मेष राशि में होता है। कुंभ योग के विषय में विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब हरिद्वार में कुंभ लगता है।

सूर्य एवं गुरू जब दोनों ही सिंह राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक (महाराष्ट्र) में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। गुरु जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब उज्जैन में कुंभ लगता है।

कुंभ में महत्वपूर्ण ग्रह : कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। सागर मंथन से जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तब अमृत घट को लेकर देवताओं और असुरों में खींचा तानी शुरू हो गयी। ऐसे में अमृत कलश से छलक कर अमृत की बूंद जहां पर गिरी वहां पर कुंभ का आयोजन किया गया।

अमृत की खींचा तानी के समय चन्द्रमा ने अमृत को बहने से बचाया। गुरू ने कलश को छुपा कर रखा। सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इन्द्र के कोप से रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तब कुंभ का अयोजन होता है। क्योंकि इन चार ग्रहों के सहयोग से अमृत की रक्षा हुई थी।

12 वर्ष नहीं हर तीसरे वर्ष लगता है कुंभ

समस्या तबतक एक समस्या है जबतक इसे एक समस्या के रूप में देखा जाता है।

गुरू एक राशि लगभग एक वर्ष रहता है। इस तरह बारह राशि में भ्रमण करते हुए उसे 12 वर्ष का समय लगता है। इसलिए हर बारह साल बाद फिर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ के लिए निर्धारित चार स्थानों में अलग–अलग स्थान पर हर तीसरे वर्ष कुंभ का अयोजन होता है। कुंभ के लिए निर्धारित चारों स्थानों में प्रयाग के कुंभ का विशेष महत्व है। हर 144 वर्ष बाद यहां महाकुंभ का आयोजन होता है।

महाकुंभ के संबंध में मान्यता : शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर बारह वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का बारह वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है इसलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का अयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है।

कुम्भ पर्व विश्व मे किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा संग्रहण है. सैंकड़ों की संख्या में लोग इस पावन पर्व में उपस्थित होते हैं. कुम्भ का संस्कृत अर्थ है कलश, ज्योतिष शास्त्र में कुम्भ राशि का भी यही चिह्न है. हिन्दू धर्म में कुम्भ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है: हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में संगम जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं.

प्रयागगराज का कुम्भ पर्व : ज्योतिषशास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुम्भ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है. प्रयाग का कुम्भ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है.

हरिद्वार के कुम्भ पर्व : हरिद्वार हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है. प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपा. वन, मायापुरी, गंगाद्वार और मोक्षद्वार आदि नामों से भी जाना जाता है. हरिद्वार की धार्मिक महत्तान विशाल है. यह हिन्दुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थान है. मेले की तिथि की गणना करने के लिए सूर्य, चन्द्र और बृहस्पति की स्थिति की आवश्यकता होती है. हरिद्वार का सम्बन्ध मेष राशि से है।

नासिक का कुम्भ पर्व : भारत में 12 में से एक जोतिर्लिंग त्र्यम्बकेश्वर नामक पवित्र शहर में स्थित है. यह स्थान नासिक से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ. 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुम्भ मेला नासिक एवं त्रयम्बकेश्वर में आयोजित होता है।

ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार नासिक उन चार स्थानों में से एक है, जहां अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं. कुम्भ मेले में सैंकड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन जल में नहा कर अपनी आत्मा की शुद्धि एवं मोक्ष के लिए प्रार्थना करते है।. यहां पर शिवरात्रि का त्यौहार भी बहुत धूम धाम से मनाया जाता है.

उज्जैन का कुम्भ पर्व : उज्जैन का अर्थ है विजय की नगरी और यह मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है. इंदौर से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है. यह शिप्रा नदी के तट पर बसा है. उज्जैन भारत के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों में से एक है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शून्य अंश (डिग्री) उज्जैन से शुरू होता है. महाभारत के अरण्य पर्व के अनुसार उज्जैन 7 पवित्र मोक्ष पुरी या सप्त पुरी में से एक है।(एजेंसी)

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।
- लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन।
- लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना।
- गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना।
- अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना।
- लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना।
- धार्मिक जागरुकता फैलाना।

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र।
मोबाइल : 9810960818 ई मेल : lokjagriti@gmail.com

पीड़ित बहाने बनाते हैं. लीडर परिणाम देते हैं।

किन्नरों के अखाड़े और उनका अस्तित्व

प्रयागराज यानी इलाहाबाद का कुंभ मेला इस बार कई वजहों से चर्चा में है। उन तमाम वजहों में से एक है– किन्नर अखाड़ा। रोशनी में डूबी कुंभनगरी में अमूमन हर शख़्स की ज़बान पर किन्नर अखाड़े का नाम है। हालांकि अखाड़ों को मान्यता देने वाली संस्था अखाड़ा परिषद इसे अखाड़ा मानने से इनकार करती है। साल 2019 के कुंभ मेले के शुभारंभ की तैयारियां ज़ोरों पर थीं, जब किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी शाही पेशवाई लेकर शहर में दाख़लि हुए।

शहर से उनकी पेशवाई निकली तो लोग पहली बार किन्नरों को इस तरह देखकर दंग थे। साल 2016 में उज्जैन कुंभ मेले से चर्चा में आए किन्नर अखाड़े ने प्रयागराज के कुंभ में जूना अखाड़े से हाथ मिलाया और उसी के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। हालांकि इस फ़ैसले को लेकर किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर और अखाड़ा प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहती हैं कि ये किन्नर अखाड़े का जूना अखाड़े में विलय नहीं है।

इस बात से जूना अखाड़े के संरक्षक हरि गिरि भी सहमत दिखते हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये कहना बिल्कुल ग़लत होगा कि किन्नर अखाड़े का जूना अखाड़े में विलय हो गया है। किन्नर अखाड़ा एक अलग संगठन है जो आगे भी रहेगा।

किन्नरों के लिए अलग से अखाड़ा बनाने की ज़रूरत के सवाल पर लक्ष्मी कहती हैं, ''किन्नर अखाड़ा बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किन्नर समुदाय का पतन सनातन धर्म से हुआ था और किसी ने उनकी सुध नहीं ली। साल 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें तीसरे जेंडर के तौर पर पहचान दी तो मुझे लगा कि किन्नरों को मान–सम्मान दिलाने के लिए धर्म से अच्छा रास्ता कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे किसी पद का लालच नहीं है, मैं खुद को इस गद्दी की वॉचमैन समझती हूं।''

उन्होंने कहा, ''जूना अखाड़ा का माइंडसेट किन्नरों के प्रति काफ़ी अच्छा रहा है और हमें जिस तरह उन्होंने अपने साथ रखा वो हमारे लिए सम्मान की बात है। हमें जूना अखाड़े ने बड़ी उदारता से अपनाया।'' किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर भवानी नाथ वाल्मीकि कहती हैं, ''अखाड़ा बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें मुख्यधारा से जुड़ना है। समाज के लोग हमें स्वीकार नहीं करते। लेकिन अपनी बात रखने और मनवाने के लिए धर्म सबसे अच्छी चीज़ है। सबको पूजा और सम्मान का अधिकार है तो किन्नर समाज के साथ भी वैसा ही बर्ताव हो।''

किन्नर अखाड़ा बनाने की बात जब शुरू हुई तो किन्नर समुदाय के लोगा. ं ने ही इसका विरोध करना शुरू किया। किन्नर समुदाय में विरोध की वजह भी धर्म है। यही नहीं, सनातन परंपरा पर बने 13 अखाड़ों ने भी शुरुआत से ही किन्नरों का अलग अखाड़ा बनाने का विरोध किया।

अखाड़ों को मान्यता देने वाली संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का मानना है कि किन्नर अखाड़ा का कोई अस्तित्व सनातन परंपरा में नहीं है और आगे चलकर भी इसे 14वें अखाड़े के तौर पर मान्यता नहीं मिलेगी।

नरेंद्र गिरि ने कहा, ''कोई किन्नर अखाड़े की मान्यता नहीं है। 13 अखाड़े हैं और 13 ही रहेंगे। वैसे भी वो जूना अखाड़े में समाहित हो गया है तो उसका कोई अस्तित्व अब रहा नहीं। किन्नर एक ऐसा समुदाय है जो किसी से अलग थोड़ी है। (एजेंसी)

शिक्षा की ज

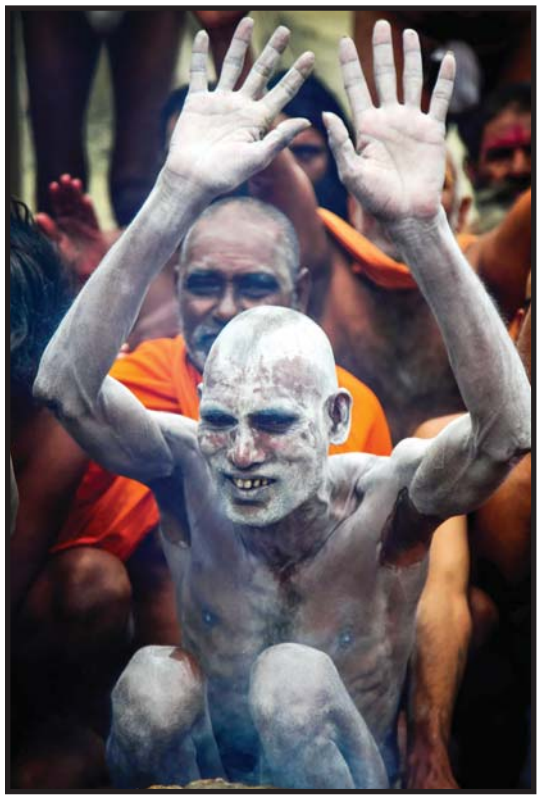

लोक जागृति

शहीदों को नमन

जम्मू कश्मीर के पुलवामामें हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा, शहीद जवानों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने श्रद्धांजलि दी।

इससे पहले पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू–कश्मीर में सेना के ऊपर यह कई दशकों में हुए हमलों में सबसे बड़ा हमला है।

दरअसल, गुरुवार को सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। इस काफिले में करीब 70 गाड़ियां थीं और 2500 जवान शामिल थे। उसी दौरान सामने से विस्फोटक से लदी एक एसयूवी कार आई और उसने सीआरपीएफ की बस में टक्कर मार दी। आतंकवादी ने जिस कार से टक्कर मारी थी, उसमें करीब 350 किलो विस्फोटक थे। इसकी वजह से विस्फोट इतना घातक हुआ कि इसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इस घटना पर पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि आतंकी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और अब उन्हें इसका अंजाम भी भुगतना होगा।

हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्त बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं, हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा था कि इस समय बड़े आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है कि वो ऐसी तबाही मचाकर, भारत को बदहाल कर सकता है। उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे नहीं होंगे। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में अलग–थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिशें रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है. उन्होंने कहा कि जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को भी मैं समझ रहा हूं। उनका पूरा अधिकार है, लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि, ये बहुत ही संवेदनशील और भावुक समय है, इसलिए राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है, ये स्वर विश्व में जाना चाहिए। (एजेंसी)

न भूलेंगे, न माफ करेंगे, बदला लेकर रहेंगे

पुलवामा हमले पर CRPF की कड़ी टिप्पणी

जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण जो हमला किया है, उस पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। पुलवामा आतंकी हमले में अपने साथियों को खोने वाले सीआरपीएफ ने स्पष्ट कह दिया है कि वह इस हमले को न भूलेगा और न ही माफ करेगा। सीआरपीएफ ने आतंकियों को कड़े लहजे में कहा है कि वह इस जघन्य हमले का बदला जरूर लेगी। सीआरपीएफ ने एक ट्वीट कर कहा कि हम न भूलेंगे और न ही माफ करेंगे। हम पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवाना. " को हम सलाम करते हैं और अपने शहीद भाइयों के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। इस जघन्य हमले का बदला लिया जाएगा।' इस ट्वीट के साथ सीआरपीएफ ने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसके माध्यम से उसने अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है।

हाथी की मूर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तल्ख

देश के संसाधनों और सरकारी खजाने को निजी जागीर समझने वाले राजनी. तिक दलों के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख राजनीतिक दलों के लिए नजीर का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता के दौरान मायावती ने पार्टी के चुनाव चिह्न हाथी और खुद की प्रतिमाएं स्थापित कराने में सरकारी खजाने से 4 हजार 184 करोड़ रूपए फूंक दिए थे। लोकायुक्त की जांच में इस सरकारी धन राशि में से 1410 करोड़ रुपए का घपला पाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका में कहा कि मायावती को जनता के धन लौटाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि मायावती जनता के पैसे का भुगतान जेब से करें। इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की गई है। राजनीतिक दलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह नजरिया कड़ा सबक साबित होगा। देश में सरकारी धन से मूर्तियों की राजनीति पर भी इससे काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। सरकारी धन को अपनी बपौती समझने वाले राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं और पार्टी का प्रचार करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मूर्तियां स्थापित कराने को खेल खूब खेला है। मायावती ने इस मामले में सारे रेकार्ड ही ध्वस्त कर दिए। बसपा चुनाव चिह्न हाथी और खुद की मूर्तियां लगाने में सारी नैतिकता–मर्यादाओं को दलितों के भले के नाम पर ताक पर रख दिया।

आम जनता के करों से मिलने वाले धन को अपनी निजी महत्वकांक्षाओं की भेंट चढ़ा दिया। इस मुद्दे पर उंगली उठाने वाले विरोधियों को दलित विरा. `धी करार देने में मायावती ने कसर बाकी नहीं रखी। मूर्तियों में उड़ाई गई इस धनराशि को यदि आम लोगों के सार्वजनिक कामों में भी नहीं तो दलितों की योजनाओं के लिए उपयोग में लिया जाता तो भी हजारों परिवारों का भला हो सकता था। दलित राग अलापने वाली मायावती ने सरकारी धन की बर्बादी में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दरअसल देश को चलाने के लिए कानून बनाने वाले राजनीतिक दल खुद को इससे ऊपर समझते हुए मनमानी करने पर उतारू रहते हैं। नेता समझते हैं कि मतदाता तो पांच साल तक कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए जैसी चाहे सरक. ारी संसाधनों की लूट मचाओ। मायावती को मिली सीख निश्चित तौर पर नेताओं को दायरे में बांधने का काम करेगी। नेताओं की मूर्तियां लगाने का यह सिल. सिला सभी राजनीतिक दलों की देन है। कांग्रेस हो या भाजपा सभी अपने चहेते नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित कराकर वोट बैंक को मजबूत करने में लगे रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में नेताओं की छवि चाहे जैसी रही हो, उनकी व्यापक तौर पर स्वीकार्यता हो

खरी-खरी

पेड़ काटेंगे गमले से
काम चलाएंगे।

जीत और हार जीवन का एक हिस्सा है, जिसे समानता के साथ देखा जाना चाहिए।

राजनीति

सुरेश पांडेय

कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान देने एवं जनता की निःस्वार्थ सेवा करने वाले श्री सुरेश पांडेय के पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें दिल्ली में जिला महासचिव नियुक्त किया गया है।

पेशे से वकील एवं लगभग 25 साल से अधिक का राजनीतिक सफर शुरुआत संगठनात्मक एनएसयूआई युवा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस में चुनाव की जिम्मेदारी कई राज्यों में पीआरओ की भूमिका निभाने के बाद एवं यूथ कांग्रेस में सेक्रेटरी के पद पर रहने के बाद आप पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी के लिए अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस भूमिका को निभाते हुए उन्होंने पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी के हर कार्यकर्ता को सम्मान दिलाने का कार्य किया है एवं पुराने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का कार्य भी पिछले 6 महीनों में बखूबी निभाया है।

दिनेश कुमार

दीपक भारद्वाज

पिछले 18 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे एनएसयूआई से शुरुआत होने के बाद एनएसयूआई में जिले में सचिव एवं प्रदेश महासचिव की भूमिका में बढ़–चढ़कर छात्र छात्रों के हितों के लिए कार्य किया, युवा कांग्रेस में लगभग 5 साल जिला उपाध्यक्ष एवं दिल्ली के प्रभारी एवं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम के साथ काम किया। वर्ष 2016 में पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय माकन जी के साथ दिल्ली के एमसीडी चुनावों में कार्य किया।

विजय त्यागी

पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में जिला पटपड़गंज के लिए चुनाव आयोग समन्वयक का कार्य एवं जिला के सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट के पद पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही के राजस्थान विधानसभा चुनावों में आईसीसी की तरफ से पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई एवं राजस्थान के राजसमंद जिले में भीम विधानसभा में 15 वर्षों के बाद पार्टी को जीत हासिल कराने में भी दीपक भारद्वाज की अहम भूमिका रही।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैंकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं। लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारण से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाऐं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.

17 मार्च 2019

होली मिलन समारोह में आप सभी आमंत्रित हैं

कवि सम्मेलन

कविगण कृपया इस नंबर पर संपर्क करें

9560222777

वैशाली, सेक्टर–3ए, PLOT NO.95

सुप्रीम कोर्ट का 'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड' पर बड़ा फैसला, बरकरार रखी संवैधानिकता

सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी कोड को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद IBC (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) की संवैधानिक मान्यता बरकरार रहेगी।सुप्रीम कोर्ट ने IBC को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बैंकिंग सचिव का कहना है कि SC का फैसला सकारात्मक है। इस फैसले से क्रेडिट व्यवहार में सुधार आएगा। अब तक IBC के तहत 70,000 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। आपको बता दें कि आईबीसी का आगाज जून 2017 में हुआ, जब आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे 12 बड़े कर्जदारों का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में ले जाएं। बैंकों के बकाया 8 लाख करोड़ रुपये का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा इन 12 कंपनियों पर बाकी था। इनमें से केवल पांच का मामला अब तक सुलझ पाया है। वेदांता ने इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स को खरीदा, एयॉन–जेएसडब्ल्यू स्टील ने मॉनेट इस्पात की बोली जीती, टाटा स्टील ने भूषण स्टील को खरीदा जबकि लैंको इंफ्रा अब कुर्की की राह पर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आईबीसी से कर्जदारों का रवैया बदलने लगा है। पेमेंट से जुड़ा अनुशासन बेहतर हुआ है क्योंकि रेगुलेटर ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आईबीसी लागू हो जाने और गड़बड़ी करने पर कंपनी पर ओनर्स का कंट्रोल खत्म हो सकने की स्थिति के कारण बर्ताव बदल रहा है। यह अच्छी बात है। प्रक्रिया में देर हो रही है, लेकिन बॉरोअर अब यह मानकर नहीं चल सकता कि क्रेडिटर उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या होता है इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड – इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड के तहत अगर कोई कंपनी कर्ज नहीं देती है तो उससे कर्ज वसूलने के लिए दो तरीके हैं। एक या तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। इसके लिए एनसीएलटी की विशेष टीम कंपनी से बात करती है। कंपनी के मैनेजमेंट के राजी होने पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्जा हो जाता है। बैंक उस असेट को किसी अन्य कंपनी को बेचकर कर्ज के पैसे वसूलता है। बेशक यह राशि कर्ज की राशि से कम होता है, मगर बैंक का पूरा कर्जा डूबता नहीं है। कर्ज वापसी का दूसरा तरीका है कि मामला एनसीएलटी में ले जाया जाए। कंपनी के मैनेजमेंट से कर्ज वापसी पर बातचीत होती है। 180 दिनों के भीतर कोई समाधान निकालना होता है। कंपनी को उसकी जमीन या संपत्ति बेचकर कर्ज चुक. ाने का विकल्प दिया जाता है। ऐसा न होने पर कंपनी को ही बेचने का फैसला किया जाता है। खास बात यह है कि जब कंपनी को बेचा जाता है तो उसका प्रमोटर या डायरेक्टर बोली नहीं लगा सकता।(एजेंसी)

देरी से चुकायी जाने वाली राशि पर ब्याज का भुगतान प्रत्याशित है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993 के तहत देरी से चुकायी जाने वाली राशि पर ब्याज का भुगतान प्रस्पेक्टिव (प्रत्याशित) है पर कोर्ट ने क़ानून के रेट्रॉस्पेक्टिव (पिछले प्रभाव) और रेट्रोऐक्टिव (अगले प्रभाव) से लागू होने के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। न्यायमूर्ति एके सीकरी, अशोक भूषण और एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला दिया। पीठ के समक्ष यह याचिका तब आइ जब न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा और अरुण मिश्रा की पीठ ने इस मामले में अलग अलग फ़ैसला दिया। न्यायमूर्ति गौडा ने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधान पिछले प्रभाव से लागू होने वाले हैं जबकि न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यह ना तो पिछले प्रभाव से है और ना ही अगले प्रभाव से बल्कि प्रत्याशित (prospective) है। पीठ इस बात पर ग़ौर कर रहा था कि क्या जब पक्षों के बीच आपूर्ति के लिए क़रार हुआ उस समय यह अधिनियम लागू हो सकता है या नहीं। यह अधिनियम 23।09।1992 को लागू हुआ। कहा गया कि यह अधिनियम का ऑपरेशन प्रत्याशित है और इसको पीछे से लागू होने वाला कहने की ज़रूरत नहीं है। पीठ ने कहा कि जब किसी क़ानून के नियम को पिछले प्रभाव से होने की बात की जाती है तो इसका मतलब यह है कि यह उन सौदों पर भी लागू होगा जिन्हें इस नियम के लागू होने से पहले पूरा किया जा चुका है। पीठ ने जय महाकाली रोलिंग मिल्ज़ बनाम भारत संघ के मामले में आए फ़ैसले का इस संदर्भ में ज़िक्र किया। इस फ़ैसले में कहा गया था कि 'रेट्रोसपेक्टिव' का मतलब है पिछले प्रभाव से३ रेट्रोसपेक्टिव क़ानून का मतलब एक ऐसा क़ानून जो पीछे देखता है या विगत की बात करता है।(एजेंसी)

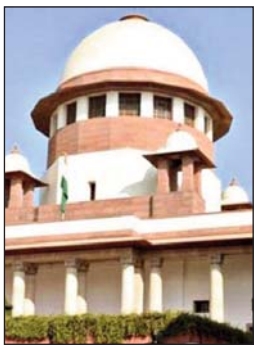

खरी-खरी

बिना पानी के शौचालय

सेवा सबसे कठिन व्रत है।

मोदी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया

भारत की राजनीति का वो दुर्लभ दिन जब विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका चाहते हुए भी नहीं निभा पाया और न चाहते हुए भी वह सरकार का समर्थन करने के लिए मजबूर हो गया, इसे क्या कहा जाए? कांग्रेस यह कह कर क्रेडिट लेने की असफल कोशिश कर रही है कि बिना उसके समर्थन के भाजपा इस बिल को पास नहीं करा सकती थी लेकिन सच्चाई यह है कि बाज़ी तो मोदी ही जीतकर ले गए हैं। "आरक्षण", देश के राजनैतिक पटल पर वो शब्द, जो पहले एक सोच बना फिर उसकी सिफारिश की गई जिसे, एक संविधान संशोधन बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया, और अन्ततः एक कानून बनाकर देश भर में लागू कर दिया गया।

आजाद भारत के राजनैतिक इतिहास में 1990 और 2019 ये दोनों ही साल बेहद अहम माने जाएंगे। क्योंकि जब 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने देश भर में भारी विरोध के बावजूद मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर "जातिगत आरक्षण" को लागू किया था तो उनका यह कदम देश में एक नई राजनैतिक परंपरा की नींव बन कर उभरा था। समाज के बंटवारे पर आधारित जातिगत विभाजित वोट बैंक की राजनी. ति की नींव।

इस लिहाज से 8 जनवरी 2019 की तारीख़ उस ऐतिहासिक दिन के रूप में याद की जाएगी जिसने उस राजनीति की नींव ही हिला दी। क्योंकि मोदी सरकार ने ना केवल संविधान में संशोधन करके, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है बल्कि भारत की राजनीति की दिशा बदलने की एक नई नींव भी रख दी है। यह जातिगत वोटबैंक आधारित राजनीति पर केवल राजनैतिक ही नहीं कूटनीतिक विजय भी है। इसे मोदी की कूटनीतिक जीत ही कहा जाएगा कि जिस वोटबैंक की राजनीति सभी विपक्षी दल अब तक कर रहे थे, आज खुद उसी का शिकार हो गए। यह वोटबैंक का गणित ही था कि देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10फीसद आरक्षण लागू करने हेतु 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक राजयसभा में भाजपा अल्पमत में होते हुए भी पारित करा ले जाती है। मोदी सरकार की हर नीति का विरोध करने वाला विपक्ष, मोदी को रोकने के लिए अपने अपने विरोधों को भुलाकर महागठबंधन तक बना कर एक होने वाला विपक्ष आज समझ ही नहीं पा रहा कि वो मोदी के इस दांव का सामना कैसे करे। अब खास बात यह है कि आरक्षण का लाभ किसी जाति या धर्म विशेष तक सीमित न होकर हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी और अन्य अनारक्षित समुदायों को मिलेगा। यह देश के समाज की दिशा और सोच बदलने वाला वाकई में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में हर विषय पर राजनीति होती है। शायद इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का यह फैसला एक राजनैतिक फैसला है जिसे केवल आगामी लोकसभा चुनावों में राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से लिया गया है। तो इन लोगों से एक प्रश्न कि देश के वर्तमान परिदृश्य में कौन–सा ऐसा राजनैतिक दल है जो राजनैतिक नफा नुकसान देखे बिना कोई कदम उठाना तो दूर की बात है, एक बयान भी देता है ? कम से कम वर्तमान सरकार का यह कदम विपक्षी दलों के उन गैर जिम्मेदाराना कदमों से तो बेहतर ही है जो देश को धर्म जाति सम्प्रदाय के नाम पर बांट कर समाज में वैमनस्य बढ़ाने का काम करते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं। याद कीजिए 1990 का वो साल जब ना सिर्फ हमारे कितने जवान बच्चे आरक्षण की आग में झुलसे थे बल्कि आरक्षण के इस कदम ने हमारे समाज को भी दो भागों में बांट कर एक दूसरे के प्रति कटुता उत्पन्न कर दी थी। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें तब देखने को मिला था जब अभी कुछ माह पहले ही सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव किया था और देश के कई हिस्से हिंसा की आग में जल उठे थे।

कहा जा सकता है कि जातिगत भेदभाव की सामाजिक खाई कम होने के बजाए बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब जाति या सम्प्रदाय सरीखे सभी भेदों को किनारे करते हुए केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई पहल का आगाज़ किया है। समय के साथ चलने के लिए समय के साथ बदलना आवश्यक होता है। आज जब आरक्षण की बात हो रही हो तो यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।

दरअसल जब देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी तो उसके मूल में समाज में पिछड़े वर्गों के साथ होने वाले अत्याचार और भेदभाव को देखते हुए उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मंडल आयोग द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थीं जिनमें से कुछ एक को संशोधन के साथ अपनाया गया था। लेकिन आज इस प्रकार का सामा. जिक भेदभाव और शोषण भारतीय समाज में लगभग नहीं के बराबर है। और आज आरक्षण जैसी सुविधा के अतिरिक्त देश के इन शोषित दलित वंचित वर्गों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव अथवा अन्याय को रोकने के लिए अनेक सशक्त एवं कठोर कानून मौजूदा न्याय व्यवस्था में लागू हैं जिनके बल पर सामाजिक पिछड़ेपन की लड़ाई हम लोग काफी हद तक जीत चुके हैं। अब लड़ाई है शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं करते हुए इसकी अलग व्यवस्था की है जो अब समाज में आरक्षण के भेदभाव को ही खत्म कर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में निश्चित रूप से मददगार होगा।(साभार : पीएस)

खरी-खरी

पहले नियुक्तिके नाम पर फिर जांच के नाम पर खाएंगे

पढाई सभी कामों में सुधार लाना सिखाती है।

जीवन सफ़र में बढ़े जा रहा हूँ...!

ठहरना न शामिल है फ़ितरत में मेरी–
मैं आब–ए–रवां हूँ बहे जा रहा हूँ,
जीवन सफ़र में बढ़े जा रहा हूँ...!

हर वक़्त जारी है जारी रहेगी–
हमेशा ही मैदान में जंग के हूँ,
हर युद्ध जीवन का मैं खूब डटकर–
बड़े ही हृदय से लड़े जा रहा हूँ,
जीवन सफ़र में बढ़े जा रहा हूँ...!

थके पाँव मेरे ग़मों के वज़न से–
मगर मेरा संघर्ष अब भी है जारी,
फ़ुर्सत मिली ना कभी बैठने की–
सफ़र में अभी भी खड़े जा रहा हूँ,
जीवन सफ़र में बढ़े जा रहा हूँ...!

विजयश्री भले मेरी संदिग्ध ही हो–
मगर जीतने की तलब है बक़ाया,
दग़ा दे गई जिस्म की क़ौत बेशक़–
मगर हौसले से अड़े जा रहा हूँ,
जीवन सफ़र में बढ़े जा रहा हूँ...!

राजेश्वर राय 'दयानिधि'

शिकायत नहीं मुझको भगवान से है–
अदावत नहीं मुझको इंसान से है,
ज़माने का भी शुक्रिया है कि उससे–
सबक़ आये दिन मैं पढ़े जा रहा हूँ,
जीवन सफ़र में बढ़े जा रहा हूँ...!

मंज़िल का भ्रम खूबसूरत है कितना–
कि ग़म रास्तों का पता ही न चलता,
शिखर छूने वाली तमन्ना लिए मैं–
निरंतर ही पर्वत चढ़े जा रहा हूँ,
जीवन सफ़र में बढ़े जा रहा हूँ...!

26 जनवरी 2019 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त प्रेमियों, ईष्टमित्रों, नगरवासियों एवं दुकानदारा भाईयों को हमारी हार्दिक शुभकामनायें।

हरीकिशन आर्य
चातक कोल्ड स्टोरेज
जीटी रोड, गुरसहायगंज
फर्म रामकिशन दयाराम एण्ड कम्पनी
जवाहर नगर गुरसहायगंज, कन्नौज
अन्य प्रतिष्ठान
चकोर भीतालय प्रा०लि०, जीटी रोड, जसोदा
चातक टायर्स, जीटी रोड, गुरसहायगंज
निवेदकः- हरीकिशन आर्य

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं
पी०के० गैस सर्विस
जी.टी. रोड गुरसहायगंज
उज्जवला योजना के तहत फ्री कनेक्शन

1-राशन कार्ड में लिखे सभी सदस्यों के आधर कार्ड।
2-आवेदक का बैंक खाता। 3-जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो।
4-फोटो-3। 5-मोबाइल नम्बर। 6-राशन कार्ड।
नोट-फार्म जमा करने के लिये आवेदक को स्वयं आना होगा।

प्रबन्धक अमित दुबे
पी०के० एजेंसीज
सराय प्रयाग-कन्नौज
डा० पी०के० कटियार
प्रोपराइटर

HP GAS

समय बदलने पर लोगों की आँखें भी बदल जाती है।

बजट में सपने ज्यादा सच कम

संतोष मिश्रा

अपने तक़रीबन एक घंटे 45 मिनट के बजट भाषण में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बॉलीवुड फ़िल्म 'उड़ीः द सर्जिकल स्ट्राइक' का ज़िक्र किया और बताया कि वो सिनेमा हॉल में दर्शकों का 'जोश' देखकर प्रभावित हुए। ये फ़िल्म कुछ साल पहले भारतीय सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फ़िल्म ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इस फ़िल्म में अंध–राष्ट्रवाद दिखाया गया है, जो लोगों को सिनेमा हॉल तक खींच पाने में सफल रहा। अगर बजट पेश होने से पहले इस बारे में थोड़ा बहुत संदेह भी था कि क्या मोदी सरकार चुनावी बजट पेश कर रही है, तो ये उसी वक़्त ख़त्म हो गया जैसे ही पीयूष गोयल ने 'उरी' का ज़िक्र किया। ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट था। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसमें अगली सरकार चुने जाने तक के ख़र्च की योजना और लेखा–जोखा था। लोकसभा चुनाव इस साल अप्रैल–मई में होने वाले हैं और उम्मीद है कि मई 2019 तक नई सरकार आ जाएगी।

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपने गढ़े माहौल को काबू में रखना पसंद है। इसलिए ज़ाहिर है उनकी सरकार ने अंतरिम बजट जैसे बेशक़ीमती मौक़े को अपने हाथ से जाने नहीं दिया।

बजट में बड़ी घोषणाएं

इस बजट में अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है– छोटे किसानों के लिए आर्थिक मदद योजना। इस योजना के तहत उन किसानों के बैंक खाते में हर साल छह हज़ार रुपए सीधे भेजे जाएंगे जिनके पास दो हेक्टेयर तक की खेती वाली ज़मीन है। किसानों को ये धनराशि साल में तीन बराबर किश्तों में दी जाएंगी। पीयूष गोयल के मुताबिक़, इस योजना का फ़ायदा देश के तक़रीबन 12 करोड़ छोटे और ग़रीब किसान परिवारों को मिलेगा। आम तौर पर एक भारतीय परिवार में औसतन पांच सदस्य होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इस स्कीम से तक़रीबन 60 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। 60 करोड़ लोग यानी वोट देने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो ये मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से थोड़ा ही कम है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो शुरू होने के बाद ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी इनकम सपोर्ट स्कीम होगी। दिलचस्प बात ये है कि यह स्कीम एक दिसंबर, 2018 यानी पिछले साल की तारीख़ से लागू मानी जाएगी और इसके तहत मिलने वाले पैसों की पहली किश्त किसानों को 31 मार्च, 2019 से पहले दे दी जाएगी। सरकार ने इस साल स्कीम के लिए 20 हज़ार करोड़ (200 अरब) रुपए का बजट तय किया है। अगले साल यह बजट बढ़ाकर 750 अरब कर दिया जाएगा। इस स्कीम के ज़रिए सरकार देश के बड़े हिस्से में उपजे कृषि संकट से निबटने की कोशिश कर रही है। ये बात और है कि वो कभी ये बात मानेगी नहीं। एक और दिलचस्प बात ये है कि इसी हफ़्ते देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर सबके लिए एक न्यूनतम आय गारंटी स्कीम लाने का वादा किया था। दूसरी तरफ़ मोदी सरकार की स्कीम में सबसे ज़्यादा मुश्किल है ये पता लगाना कि किसे स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए और किसे नहीं।

राजनीतिक तौर पर बढ़िया स्कीम

भारत के ज़्यादातर हिस्सों में ज़मीन का लेखा–जोखा बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल वही है जो हमेशा कायम रहता है– इतने सारे पैसे आएंगे कहां से? अर्थशास्त्र मानता है कि कोई भी चीज़ मुफ़्त में नहीं मिलती। अगर किसानों को ये पैसे दिए जाएंगे तो किसी न किसी को इसे ज़्यादा टैक्स के रूप में चुकाना ही होगा। इसके अलावा

स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है।

पीयूष गोयल ने देश के बड़े असंगठित क्षेत्र के लिए एक पेंशन स्कीम की घोषणा भी की। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की संख्या 42 करोड़ बताई।

इस योजना में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हज़ार रुपये पेंशन का प्रस्ताव दिया गया है। ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए होगी, जिनकी मासिक आय 15 हज़ार रुपये या इससे कम है।

हालांकि इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए लाभार्थी को अपने भी कुछ पैसे लगाने होंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले एक 18 साल के शख्स को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे।

सरकार भी उतनी ही रक़म अपनी तरफ़ से डालेगी, तभी वो 60 साल की उम्र के बाद इस पेंशन का हक़दार होगा।

अब एक बार फिर इस स्कीम को लागू करने में कई बड़ी दिक्क़तों का सामना करना पड़ेगा।

असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले एक बड़े तबके को कैश में भुगतान किया जाता है। इसके अलावा उन्हें मिलने वाले पैसों में भी बहुत असमानता है।

ऐसी स्थिति में सरकार कैसे पता लगाएगी कि किसे इस पेंशन स्कीम के दायरे में रखा जाना चाहिए और किसे नहीं।

राजनीतिक तौर पर भले ही ये एक बढ़िया स्कीम लगती हो लेकिन अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखें तो इसे लागू करना मुश्किल होगा।

मिशन 2030

वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट की परंपरा तोड़ते हुए भारतीय करदाताओं यानी मिडिल क्लास को बड़ा तोहफ़ा दिया। अगले साल से पांच लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स छूट की वर्तमान सीमा ढाई लाख रुपए है। एक अच्छा बदलाव जिस पर सरकार काम कर रही है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न को 24 घंटे के भीतर प्रोसेस करना और इसका रिफ़ंड भी 24 घंटे में ही शुरू कर देना। इसमें कोई शक़ नहीं कि अंतरिम बजट के इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए मई 2019 के आख़िर में आने वाली अगली सरकार को अपने पूर्ण बजट में इसे मंजूरी देनी होगी।

पीयूष गोयल अपने पूरे भाषण में इस बात का ध्यान रखा कि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहते रहें। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी पूरे भाषण के दौरान 'मोदी, मोदी, मोदी३' चिल्लाते रहे। गोयल ने अपनी पार्टी की उपलब्धियों की एक लंबी सूची भी पेश की और आख़िर में विज़न–2030 के नाम से 10 बिंदुओं की एक लिस्ट सामने रखी। इस लिस्ट में साल 2022 तक अंतरिक्ष में एक भारतीय को पहुंचाने, भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने (जोकि भारत लगभग पहले से ही है), भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने, भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को डिजिटल बनाने और सभी भारतीयों को पीने का साफ़ पानी दिलाने जैसी तमाम बातें शामिल थीं।

साल 2014 के आम चुनाव से पहले पीएम मोदी का चुनावी अभियान एक बेहतर भारत की उम्मीद के धागों से बुना गया था। उनका चुनावी नारा था– 'अच्छे दिन आने वाले हैं।' इसके अलावा मोदी ने नौकरियां और रोज़गार पैदा करने का वादा किया था। उन्होंने 'मिनिमम गवर्मेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस' के फ़ॉर्मूले पर चलने का वादा भी किया था। पांच साल बाद पता चला कि 'अच्छे दिन' भी किसी आम चुनावी नारे जैसा ही था। लीक हुई एक सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि नोटबंदी जैसी नाकामयाब और बेढंगे तरीके से जीएसटी लागू करने के बाद भारत में बेरोज़गारी का स्तर पिछले 46 सालों में सबसे ऊपर पहुंच गया। हालांकि अधिकारियों ने बाद में कहा कि ये एक खाका भर है, आखिरी रिपोर्ट नहीं।

नौकरियों के सवाल से सरकार बचना क्यों चाहती?

युवाओं की बेरोज़गारी का आंकड़ा 13–27 फीसद के बीच है। इससे हर साल काम में लगने वाले युवाओं की संख्या (1–1।2 करोड़) तेज़ी से नीचे गिरी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी नाम की एक निजी संस्था का कहना है कि साल 2018 में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने अपनी नौकरियां खोईं। खाने की चीजों के दामों में तेज़ी से बढ़त का नतीजा विशाल कृषि संकट के रूप में देखने को मिला। इसका प्रमाण है देश के हर हिस्से में लगातार होने वाले किसानों के विरोध प्रदर्शन। इन सबके बावजूद सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि देश में नौकरियों की कमी है।

साभार : इंटरनेट

प्रत्येक स्थान और समय बोलने योग्य नहीं रहते।

क्या है नागरिकता (संशोधन) विधेयक?

सुरेश पांडेय

केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दिये जाने के बाद इसका लोकसभा में पारित होना तय हो गया है। हालांकि विधेयक की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी जहां राजग अल्पमत में है। और जब इस विधेयक पर भाजपा को अपने सहयोगी दलों शिवसेना, जदयू, लोजपा आदि का ही समर्थन प्राप्त नहीं है साथ ही असम गण परिषद ने इस विधेयक के विरोध में भाजपा को दिया गया समर्थन वापस ले लिया है तो यह तय है कि संसद के ऊपरी सदन में इस विधेयक की राह बाधित होगी ही। यह विधेयक 2016 में पहली बार पेश किया गया था लेकिन सरकार का कहना है कि इसका मसौदा दोबारा से तैयार किया गया है। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों में इसका वायदा किया था।

नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में नागरिकता विधेयक लाया गया था। इस विधेयक के जरिये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों– हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को बिना समुचित दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इसमें भारत में उनके निवास के समय को 12 वर्ष के बजाय छह वर्ष करने का प्रावधान है। यानी अब ये शरणार्थी 6 साल बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बिल के तहत सरकार अवैध प्रवासियों की परिभाषा बदलने के प्रयास में है।

वैसे देखा जाये तो एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल एक–दूसरे के विरोधाभासी हैं क्योंकि जहां एक ओर नागरिकता संशोधन विधेयक में भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर शरणार्थियों को नागरिकता देने पर विचार कर रही हैं वहीं एनआरसी में धर्म के आधार पर शरणार्थियों को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस, शिवसेना, जदयू, असम गण परिषद और तृणमूल कांग्रेस इस विधेयक के विरोध में हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह 1985 के 'ऐतिहासिक असम करार' के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसके मुताबिक 1971 के बाद बांग्लादेश से आए सभी अवैध विदेशी नागरिकों को वहां से निर्वासित किया जाएगा भले ही उनका धर्म कुछ भी हो।

दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा जब गत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असम दौरे के दौरान लोगों को भरोसा दिलाया कि एनआरसी से कोई भी असल नागरिक नहीं छूटेगा। उन्होंने कहा कि अतीत में हुए अन्याय को दूर करने के लिए जल्द ही संसद में नागरिकता विधेयक को पारित कराया जायेगा। मोदी ने कालीनगर में 'विजय संकल्प समावेश रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि वह एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के दौरान कई लोगों को हुई दिक्कतों और समस्याओं के बारे में जानते हैं।

उन्होंने पूर्वोत्तर में भाजपा की लोकसभा चुनाव प्रचार मुहिम की शुरूआत करते हुए कहा, ''मैं आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा। दशकों से लटकी समस्या का अब अंत होने वाला है और यह आप लोगों के त्याग के कारण संभव हो पाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी लोगों को सुना जाए और वे प्रक्रिया में कम से कम कठिनाई का सामना करें।'' मोदी ने कहा था, ''नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार आगे बढ़ रही है।'' उन्होंने कहा, ''यह (विधेयक) लोगों की जिंदगी और भावनाओं से जुड़ा है। यह किसी के फायदे के लिए नहीं है बल्कि अतीत में हुए अन्याय का प्रायश्चित करने के लिए है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 35 वर्षों से ''लटके'' असम समझौते की धारा छह को लागू करने का निर्णय लिया है।

भाजपा का तर्क

असम के वरिष्ठ मंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्व शर्मा के मुताबिक अगर नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित नहीं हुआ तो अगले पांच साल में राज्य के हिंदू अल्पसंख्यक बन जायेंगे। शर्मा ने कहा कि यह उन लोगों के लिये फायदेमंद होगा जो चाहते हैं कि असम दूसरा कश्मीर बन जाये। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा, ''मुझे पूरा यकीन है कि अगर यह विधेयक पारित नहीं हुआ तो असमी हिंदू महज पांच साल में ही अल्पसंख्यक बन जायेंगे। यह उन तत्वों के लिये फायदेमंद होगा जो चाहते हैं कि असम दूसरा कश्मीर बन जाये।''

नागरिकता संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अंतिम रिपोर्ट में कम से कम चार विपक्षी दलों की सहमति नहीं है और इस समिति में उनके प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट में अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, माकपा और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में अपनी असहमति दर्ज करायी है। असहमति भरे नोट में से एक में कहा गया है, ''नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 पर संयुक्त समिति के सदस्य के तौर पर हम कह सकते हैं कि अंतिम रिपोर्ट में समिति में आम सहमति नहीं थी। हम इस विधेयक के विरुद्ध हैं क्योंकि यह असम में जातीय विभाजन को सतह पर लाता है।'' जेपीसी रिपोर्ट को बहुमत से तैयार किया गया है क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने धार्मिक आधार पर नागरिकता देने का विरोध किया था और कहा था कि यह संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती कटुता के बीच उसकी सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि वह संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। पार्टी नेता संजय राउत ने एक बयान में कहा कि असम गण परिषद ने शिवसेना से इस कानून का विरोध करने की अपील की थी जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

खरी-खरी

रामदेव जी के काले धन का आंकड़े की फाइल गायब

सबसे उत्कृष्ट दान ज्ञान–दान है।

आखिर क्यों उलझी ममता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई की कार्यवाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठीं तो 12 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। उस वक़्त विपक्ष में रहते तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी हुगली ज़िले के सिंगूर में टाटा की लखटकिया नैनो प्रोजेक्ट के लिए ली गई किसानों की जमीन लौटाने की मांग में 25 दिनों तक यहां भूख हड़ताल पर बैठी थीं। हालांकि सुप्रीम की दखल के बाद मुख्यमंत्री ने धरना समाप्त कर दिया।

वो मुख्यमंत्री के तौर पर कोलकाता पुलिस के आयुक्त राजीव कुमार से चिटफ़ंड घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की सीबीआई की कोशिशों के विरोध में धरने पर बैठी थी।

4 फरवरी को राज्य के विधानसभा में बजट पेश होना था। उससे पहले कैबिनेट की पारंपरिक बैठक भी अब धरनास्थल के पास बने एक कमरे में हुई। बजट पेश होने के दौरान भी ममता सदन में होने की बजाय धरने पर थी।

एक पुलिस अधिकारी के बचाव में इस तरह किसी मुख्यमंत्री के धरना देने की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी तरफ 3 फरवरी की शाम उस अधिकारी के घर से बाहर पुलिस के जवानों और वहां पहुंची सीबीआई के अधिकारियों के बीच जिस तरह कहासुनी और धक्का–मुक्की हुई, उसकी भी दूसरी कोई मिसाल मुश्किल है। मोदी, शाह से लेकर डोभाल तक निशाना पर

इस मुद्दे पर केंद्र और बंगाल सरकार आमने–सामने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चिटफ़ंड घोटाले की जांच तो बस एक बहाना है. अब ममता के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हैं। वैसे, ऐसे किसी टकराव की सुगबुगाहट तो लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन 2 फरवरी को बंगाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के हमलावर रवैये और उसके ठीक अगले दिन ही सीबीआई टीम का पुलिस आयुक्त के घर पहुंचते ही यह टकराव चरम पर पहुंच गया। कोलकाता पुलिस के रवैए के विरोध में सीबीआई ने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फ़ैसला किया है।

दूसरी तरफ़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस गतिरोध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को ज़िम्मेदार ठहराते हुए देश और संविधान बचाने के लिए धरने पर बैठी गई थीं। तृणमूल कांग्रेस ने 4 फरवरी को पूरे राज्य में विरोध जुलूस निकालने का भी फ़ैसला किया।

कोलकाता पुलिस और सीबीआई भी आमने–सामने

सीबीआई के अधिकारियों ने 2 फरवरी को कहा था कि पुलिस आयुक्त लापता हैं और बार–बार समन भेजने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन 3 फरवरी सुबह ममता ने अपने एक ट्वीट में भाजपा पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राजीव कुमार को दुनिया के सबसे बेहतरीन अधिकारियों में से एक बताया था।

कोलकाता पुलिस की ओर से जारी एक बयान में भी सीबीआई के आरोपों को निराधार बताया गया था। 3 फरवरी शाम को ही पुलिस आयुक्त के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस के जवानों के अलावा कई अधिकारियों की तैनाती की गई थी। (एजेंसी)

खरी-खरी

आरक्षण रुपी बूटी से बेरोजगारी समाप्त

अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक सदी से अब तक भारत के विश्वविद्यालयों में सदैव एक सम्मानित स्थान पाया है। सितम्बर 23, 1887 में स्थापित यह विश्वविद्यालय कोलकाता, मुम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय के बाद भारत का चौथा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद में एक बृहद केंद्रीय कॉलिज को आखिरकार एक विश्वविद्यालय में विकसित करने की कल्पना का श्रेय संघ प्रांतों के तत्कालीन उप राज्यपाल सर विलियम मुइर को जाता है। उनकी पहल के परिणामस्वरुप मुइर सेंट्रल कॉलिज (जिसका नामंकरण उनके बाद किया गया) की आधारशिला महामहिम लॉर्ड नोर्थब्रूक के कर कमलों द्वारा 9 दिस्मबर, 1873 में रखी गई थी। 23 सितम्बर, 1887 को अधिनियम XVIII पारित किया गया था जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कोलकाता, मुम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की तरह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी एक डिग्री प्रदान करने

विश्वविद्यालय की समस्या को लेकर अखिल भारतीय बुद्धिजीवी मंच के संयोजक डा. रजनीश पांडेय एवं राजेश कुमार ने मंत्री एवं सांसदों से मुलाकात की।

वाली संस्था के रुप में प्रारंभ किया गया था। इसकी प्रथम प्रवेश परीक्षा मार्च, 1889 में अयोजित की गई थी। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को आगरा एंव अवध के संयुक्त प्रांतों, बराड, अजमेर, और राजपुताना के अधिनियम राज्यों सहित केंद्रिय प्रांतों और केंद्रीय भारतीय एजेंसियों तक सीमित कर दिया। वर्ष 1887 और 1927 के बीच इस क्षेत्र की कम से कम अडतीस विभिन्न संस्थाओं और कॉलिजों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंद्ध किया गया था। वर्ष 1921 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राख्यापन से, मुइर सेंट्रल कॉलिज का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। वर्ष 1922–27 के बीच विश्वविद्यालय के अपने आंतरिक और बाह्य स्कंय थे जिन्हें बाद में विश्वविद्यालय को विशुध्दतः ऐकिक कर दिया और आवासीय स्वरुप प्रदान कर दिया। वस्तुतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय 5240/– रुपये के प्रारंभिक ऋण से आरंभ किया गया था जो इसके व्ययों की प्रतिपुर्ति के लिए सरकार से लिया गया था। इस ऋण की अदायर्ग दो वर्षों में की गई थी।

प्रो. रतन लाल हंगलू ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें ईमानदारी से कार्य करना एक चुनौती है। कुलपति इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। यहां भाई भतीजावाद हावी है जिसक. ो तोड़ पाना मुश्किल है। कुलपति पर कई सवाल उठ रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि जब कई प्रक्रिया के बाद कुलपति की नियुक्ति की जाती है वह भी तीन वर्ष के लिए तो बीच में सरकार द्वारा उसी के ऊपर शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

एक झूठ हजार सच्चाइयों का नाश कर देता है।

दुनिया को देश की ताकत दिखाई

हर साल की तरह इस साल भी पूरी दुनिया को देश की ताकत दिखाई दी, साथ ही हमारी विविधता में एकता की प्रतीक झांकिया लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और वायुसेना ने हवा में अपने करतब दिखाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अमर जवान ज्योति जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीन सर्विस चीफ थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। पीएम के बाद अरुण जेटली समेत अन्य मंत्रियों ने लोगों को बधाई दी।

राजपथ पर टी–90 टैंक ने राष्ट्रपति को सलामी दी। इस समय यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। सर्फेस माइन्स क्लीयरिंग सिस्टम चारों दिशाओं में घूमकर वार कर सकता है।

सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया।

लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने आज राजपथ पर इतिहास रच दिया। उन्होंने भारतीय सेना की सर्विस कॉर्प्स का नेतृत्व किया। दिलचस्प बात यह है कि इस मार्चिंग कंटिनजेंट में उनके अलावा कोई महिला जवान शामिल नहीं थी। वह भारत के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं।

गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस बार 22 झांकियों को चुना गया है। सबसे खास बात यह है कि 11 साल बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की झांकी को शामिल किया गया।

भारत–तिब्बत सीमा पर 18 हजार फीट की ऊंचाई पर जवानों ने गणतंत्र दिवस मनाया। यहां का तापमान –30 डिग्री सेल्सियस है।

कई राज्यों की झांकी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की झलक दिखाई दी। ऐसा इसलिए क्योंकि गणतंत्र दिवस आयोजन की थीम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विपक्षी नेताओं ने भी शिरकत की। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देव गौड़ा भी शामिल थे।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने बांग्लादेशी समकक्ष को पश्चिम बंगाल की सिलिगुड़ी सीमा के पास स्थित भारत–बांग्लादेश सीमा पर मिठाई दी।(एजेंसी)

एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलती को देख अपनी गलती सुधारता है।

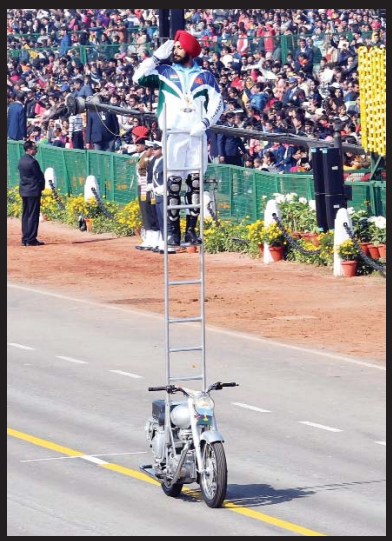

सबसे खराब अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बेहद सरल बनाकर दिखाया

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को पहली जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अब तक इसने पूरे 18 महीने पूरे कर लिये हैं। लेकिन इसकी आलोचना वो लोग कर रहे हैं जिन्हें इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। कुछ तो जानबूझकर किसी खास इरादे से भी कर रहे हैं। आइए देखें इसका प्रदर्शन कैसा रहा।

भारत में दुनिया की सबसे खराब अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी। केन्द्र और राज्य सरकारों को भी कई तरह के टैक्स लगाने के अधिकार थे। कुल मिलाकर 17 तरह के टैक्स थे। इसलिए किसी भी कारोबारी को 17 इंसपेक्टरों, 17 रिटर्न और 17 एसेसमेंट से जूझना पड़ता था। इसके अलावा टैक्स की दरें बहुत ऊंची थीं। वैट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सामान्य दरें क्रमशः 14।5% फीसद और 12.5% थीं। इतना ही नहीं, इन पर सीएसटी भी लगता था और अंततः टैक्स दर अधिकतर वस्तुओं पर 31 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी। करदाता के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह ऊंची दरों पर टैक्स दे या फिर उसकी चोरी करे। उस समय टैक्स की चोरी बड़े पैमाने पर होती थी। भारत में कई तरह के बाज़ार थे। हर राज्य एक अलग तरह का बाज़ार था क्योंकि वहां टैक्स की दरें अलग–अलग थीं। अंतर्राज्यीय टैक्स अप्रभावी हो गए क्योंकि ट्रकों को राज्यों की सीमाओं पर घंटों और कई बार तो कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था।

जीएसटी लागू होने के दिन से ही हालात में आमूल–चूल परिवर्तन आया। सभी 17 टैक्सों का एकीकरण हो गया। पूरा भारत एक बाज़ार हो गया। अंतरराज्यीय नाके हटा दिए गए। इंट्री टैक्स खात्मे के बाद शहरों में इंट्री सुगम हो गई। विभिन्न राज्य मनोरंजन के नाम पर 35% से 110% तक टैक्स वसूल रहे थे। इसमें भारी कमी हुई। 235 आयटमों पर पहले या तो 31 प्रतिशत टैक्स लग रहा था या उससे भी ज्यादा। इनमें से 10 को छोड़कर सभी पर टैक्स तुरंत घटाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया। उन 10 आयटमों पर तो टैक्स घटाकर और भी कम यानी 18 प्रतिशत कर दिया गया।

बहुत थोड़े समय के लिए कई स्लैब बनाए गए थे ताकि किसी भी वस्तु की कीमत ऊपर जाने ना पाए। इससे कीमतें बढ़ने से रुक गईं। आम आदमी के इस्तेमाल की वस्तुएं शून्य या 5% टैक्स दायरे में लाई गईं। रिटर्न ऑनलाइन हो गए, एसेसमेंट भी ऑनलाइन हो गया और इंसपेक्टरों की फौज गायब हो गई। राज्यों को गारंटी दी गई कि पहले 5 सालों के लिए उन्हें उनके राजस्व में 14% की बढ़ोतरी होगी। यह अक्सर कहा जाता है कि राजस्व की स्थिति निराशाजनक है। ऐसी टिप्पणी का मुख्य कारण राजस्व के लक्ष्य तथा राजस्व में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी न होना है।(एजेंसी)

वकीलों की देशव्यापी हड़ताल से कामकाज प्रभावित

नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के आह्वान पर देशभर के वकीलों ने हड़ताल रखी, जिससे अदालतों का कामकाज प्रभावित हुआ। वकील दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहेंगे। वकीलों का विरोध उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक, 2010 के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन रेग्यूलेटरी अथॉरिटी सहित चार प्रस्तावित विधेयकों को लेकर है। उनका आरोप है कि इससे देश में विदेशी विधि संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और बीसीआई की स्वायत्तता भी प्रभावित होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली बार एसोसिएशन तथा यहां की जिला अदालतों के बार संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष आरएन वत्स ने बताया कि हड़ताल से दिल्ली की छह जिला अदालतों– पटियाला हाउस, तीस हजारी, रोहिणी, द्वारका, साकेत तथा कड़कड़डूमा की अदालतों में कामकाज प्रभावित हुआ है।

उत्तर प्रदेश में बीसीआई के आह्वान पर लाखों वकीलों ने न्यायालयी कामकाज का बहिष्कार किया। वकीलों ने सड़कों पर उतकर प्रस्तावित विधेयकों की प्रतियां जलाई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य उमेश नारायण शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि इस प्रस्तावित विधेयक से बार काउंसिल के अधिकारों में कटौती होगी। इसे कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। बिहार में करीब एक लाख वकीलों ने अदालती कामकाज को बाधित किया। पटना में वकीलों ने डाक बंगला चौराहे पर विधेयकों की प्रतियां जलाई और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल का पुतला दहन किया। इसके बाद वकीलों ने मानव शृंखला बनाकर सड़क जाम किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधि एवं विधायी प्रकोष्ठ के वकीलों ने भी पटना उच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया। पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र चंद्र वर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे। पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में भी वकीलों ने हड़ताल रखी, जिससे निचली अदालतों तथा उच्च न्यायालयों में कामकाज बाधित हुआ। गुवाहाटी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पिजूश बिश्वास ने पूर्वोत्तर के राज्यों में हड़ताल को पूरी तरह सफल करार देते हुए अगरतला में कहा, "विधेयकों से बीसीआई तथा इसके सदस्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी।(एजेंसी)

मौन महान शक्ति का एक स्रोत है।

समाजसेवी लालजी भाई एवं डायमंड व्यापारी धानजी भाई सूरत को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी।

भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी यूपी के उपाध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी।

जनरल बिपिन रावत का स्वागत करते लोक जागृति पत्रिका के संपादक आलोक सोलंकी।

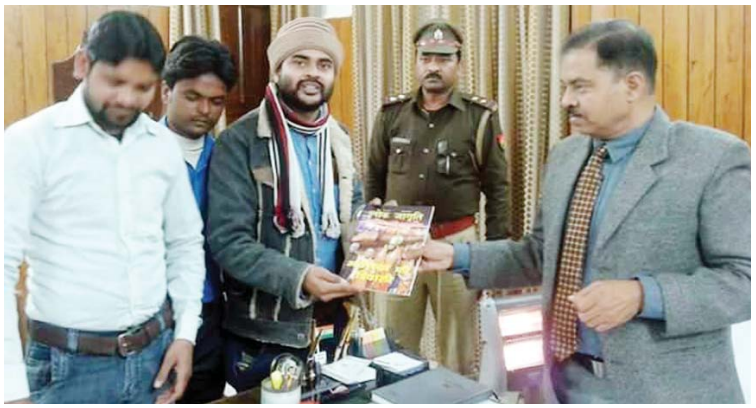

एडीजी कानपुर अविनाश चंद्र को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी।

योगेंद्र चंद को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी।

मेयर विपिन बिहारी को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते एडिटर आलोक सोलंकी।

आर्य भाषा (हिन्दी) ही भारत की राष्ट्रभाषा है।

CONSULT and LEARN

(Also online)

Astrology, Palmistry & Vaastu

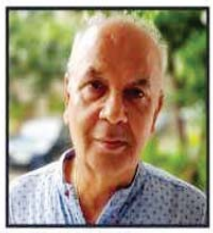

with Senior Jyotish Acharya

S.K. Sharma

27+ Yrs. Exp., Award Winner

CONSULTATIONS : On any issues of your life along with Vedic Astro, Gems, Vaastu and Vedic Mantras Guidelines for Self Chatting the Mantras to get good results against problems, Vaastu visits for Vaastu Corrections to remove Vaastu doshas without any demolitions of structure

TEACHING: Astrology, Palmistry, Numerology, Vaastu and Fengshui in short durations of time from root level to expert level. Please visit following website for more details www.astropalmistvaastuguru.com

Indirapuram : T-12 (Third floor), Module-9, Mangalam Residency, Abhay Khand-3, Indirapuram, Gzb.

Gurgaon : Flat No. 1, Tower 2, Vipulgreen Society, Sohna Road, Sec-48

Mob. No.: 9818952437, 8745824922

E-mail: astrogurusks@gmail.com, Web.: www.astropalmistvaastuguru.com

Please visit "YOU TUBE", type Astrologer S.K. Sharma for More Details

गौ रक्षा हेल्पलाइन परिवार का संकल्प

कामधेनु पंचगव्य क्रान्ति के माध्यम से घर-घर गऊ उत्पाद पहुंचाना है

Alok Solanki
Chairman
+91-9990927493

अगर सरकार को बीफ एक्सपोर्ट से इन्कम नजर आती है तो गऊ उत्पाद से हजारों करोड़ का लाभ सरकार को नजर क्यों नहीं आता, क्या आप इस संकल्प में हमारे साथ हैं?

KAMDHENU

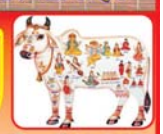

International Panchgavya Research & Marketing Pvt. Ltd.

A Unit of gramin Vikas And Gau Sewa Sansthan

✦ Cosmetics ✦ Dairy ✦ Medicines

✤ Desi Ghee ✤ Dhoop Batti ✤ Gau Nyle ✤ Shampoo ✤ Soaps ✤ Toothpaste ✤ Gobar Ke Ganpati ✤ Gobar Ki Tiles ✤ Gobar Ke Kande ✤ Organic-Haldi ✤ besan ✤ Honey

गौ रक्षा हेल्पलाइन से जुड़ने हेतु सम्पर्क करें : 8800130057
www.cowhelpline.com

011-65656528, 8800130057

गौ-रक्षा हेल्पलाइन : 011-6565-6464, पंचगव्य हेल्प लाइन नं. : 9999092304

EDUCATION SOLUTION

Education Solution

One Door Solution For All Educational Needs

Save Your Years and Regularise Your Studies with "NIOS" Board
Home Tuition Assignments Are Also Provided at Affordable Cost

Complete Your Syllabus in Summer Vacation

Now in Indirapuram Niti Khand -1

Abacus Classes Also Available

ACADEMIC COACHING

Ist - VIIIth	XIth - XIIth	B.Com, B.A-B.Sc
MATHS, SCIENCE, ENGLISH, HINDI, S.ST.	MATHS, PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY, ENGLISH, ACCOUNTS, ECONOMICS, B.st, C++, I.P.	ACCOUNT, ECONOMICS, MATHS, INCOME TAX, CORP. ACCOUNTING, BUSINESS LAW, COST ACCOUNTING
IXth - Xth		
MATHS, SCIENCE, ENGLISH, HINDI, S.ST.		

PROFESSIONAL COACHING

CA-CPT,CS,ICWA	BBA, MBA	B.Tech, MBBS
CA-CPT, IPCC CS (Foundation) CS (Executive) CMA (Foundation) CMA (Inter Mediate)	INCOME TAX, COSTING FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATE ACCOUNTING FINANCIAL ACCOUNTING BUSINESS LAW	IIT-JEE, BITSAT CPMT, UPTECH **Competitive Exam** POLYTECHNIC BANK ENTRANCE, UPSE SSC, SPOKEN ENGLISH, ETC.

HEAD OFFICE : PLOT NO 420 SECTOR 5 VAISHALI GHAZIABAD, BEHIND SHOPRIX MALL

Office : 0120-4130999 | M. : 9911932244, 9999232199, 9999207099, 9999907099

Email: educationsolutionvep@gmail.com | www.educationsolution.co

जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

ताहिर हुसैन सिद्दीकी
पूर्व विधायक

जुनैद सिद्दीकी
जिलाध्यक्ष-युवा उद्योग व्यापार मण्डल-कन्नौज

तहसीन सिद्दीकी
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष-फर्रु०

आप सभी जनपदवासियों, ईष्टमित्रों एवं कार्यकर्ताओं को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

जमालुद्दीन सिद्दीकी
विधायक
भोजपुर-फर्रुखाबाद

राशिद जमाल सिद्दीकी

अरशद जमाल सिद्दीकी
पूर्व जिलाध्यक्ष सपा-कन्नौज

ब्लाक प्रमुख
कमालगंज-फर्रु.

निवेदक-दिलपसन्द बीड़ी कम्पनी, दिल पसंद फ्लोर मिल एवं स्वागत आटा
गाँधी नगर गुरसहायगंज-कन्नौज

RNI NO.UPHIN/2011/39809

LEGEAZY
INTERNATIONAL
FREEDOM OF LIFE

Legeazy membership is a unique concept which provides consultancy without any hassle, Free of cost and with trusted qualified professionals

* Personal legal assistance
* Commercial & consumer dispute
* Corporate matters Income Tax and service tax mattters.
* Regd. of Company, Service Tax, Trust, society trade mark etc.
* Property documentation, Validation, title investigation and Advise.
* Criminal and civil matters.
* Builders buyers disputes.
* Family disputes and consultancy on marital discords.
* Accounting/Book Keeping.
* Claims and Settlement.

Off. Add:- 3A/95, Vaishali Ghaziabad, U.P. 201010
Mob. No.:-9560522777, 9810960818
Email: info@legeazy.com Website : www.legeazy.com